

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर

समक्ष : एम०के०सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 3508-एक/2015 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक 21.10.2015 - पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना - प्रकरण क्रमांक 117/2014-15 अपील

1- केदार 2- रामप्रकाश 3- मुन्नालाल  
4- रामलखन 5- तुलाराम 6- सभाराम  
सभी पुत्रगण जानकारी प्रसाद वघेले,  
निवासी कछपुरा मौजा खिरैठा  
तहसील अम्वाह जिला मुरैना  
विरुद्ध

--- आवेदकगण

1- कु०प्रेमवती 2- कु०गुडडी 3- कु०रामदुलारी  
4- कु०रामसखी पुत्रियों फुँदी वघेले  
निवासी कछपुरा मौजा खिरैठा  
तहसील अम्वाह जिला मुरैना

--- अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री सुनील जादौन अभिभाषक)  
(अनावेदकगण की ओर से श्री बी०एस०धाकड़ अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 10 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-15 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि ग्राम खिरैठा तहसील अम्वाह स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 93 रकबा 0.30 है., 95 रकबा 0.80 हैक्टर,




96 रकबा 0.80 हैक्टर, 97 रकबा 0.50 हैक्टर आवेदकगण एवं अनावेदक के नाम हिस्सा 1/2 पर शासकीय अभिलेख में अंकित है। आवेदकगण ने नायब तहसीलदार वृत्त दिमनी तहसील अम्वाह के समक्ष आवेदन देकर अनोदकगण के हिस्से की भूमि पर स्वयं का कब्जा दर्ज करने की मांग करने पर प्रकरण क्रमांक 81/13-14 बी 121 पंजीबद्ध किया गया तथा अनावेदकगण की अनुपस्थिति के कारण आदेश दिनांक 27-12-2014 पारित करके आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये गये। नायब तहसीलदार वृत्त दिमनी तहसील अम्वाह के प्रकरण क्रमांक 81/13-14 बी 121 में पारित दिनांक 27-12-2014 के विरुद्ध अनावेदकगण ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष दिनांक 13-7-15 को प्रस्तुत की एवं विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने प्रकरण क्रमांक 117/14-15 अपील में हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 21-10-15 पारित किया एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करके प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया। इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि ग्राम खिरैटा तहसील अम्वाह स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 93 रकबा 0.30 है., 95 रकबा 0.80 हैक्टर, 96 रकबा 0.80 हैक्टर, 97 रकबा 0.50 हैक्टर के संपूर्ण भू भाग पर आवेदकगण का कब्जा चला आ रहा है एवं अनावेदकगण कभी खेती करने नहीं गई हैं आवेदकगण खेती कर रहे हैं जैसाकि तहसील न्यायालय में आई साक्ष्य से एवं राजस्व निरीक्षक व

1/12



पटवारी द्वारा मौके पर की गई जांच एवं पूछताछ से प्रमाणित हुआ है । अनावेदकगण तहसील न्यायालय में इसीलिये अनुपस्थित रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उक्त भूमि से उनका कोई वास्ता नहीं है तहसील न्यायालय का आदेश सही है । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-12-2014 के विरुद्ध लम्बे समय वाद अपील की गई है। लम्बे समय तक आवेदकगण का वाद विचारित भूमि पर कब्जा होने से उनके कब्जे को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी ने बेरूम्याद अपील में विलम्ब क्षमा करके पक्षकारों के बीच मुकदमेवाजी बढ़ाई है । उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत कर बताया है कि अनावेदिकाओं के खिलाफ नायब तहसीलदार ने एकपक्षीय कार्यवाही करके आदेश दिया है। जब अनावेदकगण बाजरा की फसल बोन 6-7-15 को खेतों पर गई तब उन्हें आवेदकगण ने रोक दिया व झगड़ा करने लगे। इसके वाद पता करने पर नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी होने पर प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर जानकारी के दिन से समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने ठीक ही समयावधि में प्रस्तुत होना माना है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायब तहसीलदार वृत्त दिमनी तहसील अम्वाह के प्रकरण क्रमांक 81/13-14 बी 121 में पारित दिनांक 27-12-2014 के विरुद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष दिनांक 13-7-15 को अपील प्रस्तुत की है । यह तथ्य भी निर्विवाद है कि नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है तब क्या





अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की है ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-47 एवं परिसीमा अधिनियम 1963-धारा-5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है - उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।

2. परिसीमा अधिनियम 1963-धारा-5 एवं भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-47 - सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एवं पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रुख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

उपरोक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 117/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-15 से अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-10-15 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अम्वाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 117/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-10-15 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।





(एम0के0सिंह)  
सदस्य

राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर